जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में संचार माध्यमों का योगदान

(बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के विशेष संदर्भ में)

▫ अर्चना भारती

सारांश :- **स्वतंत्रता के पश्चात् देश में महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति समाज में जागरूकता, संवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में अनेक कार्यक्रम संचालित किए गए। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने एवं संस्थागत प्रसव को प्रौन्नत करके सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1 जून, 2011 को 'जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम' (जे.एस.एस.के.) की शुरुआत की। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को प्रभावी कार्यान्वयन एवं सर्वसाधारण जानकारी एवं जनता के बीच प्रचार-प्रसार हेतु जिला स्तर से विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा सूचना, शिक्षा, और संप्रेषण का काम संचालित किया जा रहा है। संचार माध्यमों के प्रचार-प्रसार के कारण कार्यक्रम के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है तथा अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ उठा रहे हैं। बिहार में मातृ मृत्यु दर में काफी तेजी से गिरावट हुई है। सुरक्षित प्रसव एवं संस्थागत प्रसव में भी सुधार देखा गया है, लेकिन राष्ट्रीय औसत से तुलना की जाए तो राज्य का मातृ मृत्यु दर काफी अधिक है। बिहार में कुपोषण, खून की कमी के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव मातृ मृत्यु दर की प्रमुख वजह है। हालांकि मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए राज्य सरकारें हर संभव प्रयास कर रही है। परन्तु जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के प्रति संचार माध्यमों द्वारा चलाए जा रहे प्रचार-प्रसार की गतिविधियों का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है।**

महत्वपूर्ण शब्द :- **संचार माध्यम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रचार-प्रसार, मातृ मृत्यु।**

प्रस्तावना

भारत में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं की कमी, प्रशिक्षित शिक्षाकर्मियों का अभाव एवं महिला चिकित्सकों की अनुपस्थिति के कारण ग्रामीण महिलाओं में मातृ मृत्यु दर अधिक है। मातृ मृत्यु का अर्थ है गर्भावस्था के दौरान अथवा प्रसव के 42 दिन उपरांत तक के अंदर होने वाली मृत्यु। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं होने के कारण किशोरावस्था में ही स्त्री गर्भवती हो जाती है। विश्व स्तर पर हर वर्ष 60 हजार से अधिक गर्भवती महिलाओं की मृत्यु आयरन की कमी के कारण होती है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी आंकड़ों में कहा गया है कि वर्ष 2010 में भारत में लगभग 57000 गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (2000) में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, मातृत्व स्वास्थ्य एवं गंभीर बीमारियों के नियंत्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वर्ष 2017 तक मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1,00,000 जीवित शिशुओं के जन्म पर 100 निर्धारित किया गया है। भारत ने पिछले दो दशकों में मातृ मृत्यु दर कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत में 1990 में मातृ मृत्यु दर काफी अधिक थी। वर्ष 1990 की 560 आधार रेखा से, राष्ट्र ने वर्ष 2010-12 तक आते-आते 178 की दर प्राप्त कर ली और वर्ष 2015 तक गिरावट की इस दर के 141 मातृ मृत्यु अनुपात तक पहुंचने का अनुमान है। भारत के 8 राज्यों-उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान और असम में मातृ मृत्यु दर अधिक है। हालांकि इन राज्यों में मातृ मृत्यु अनुपात में लगातार कमी हुई है, लेकिन राष्ट्रीय औसत से बेहतर बनाने की जरूरत है। गरीब राज्यों में बिहार में सबसे कम मातृ मृत्यु दर दर्ज की गई है। नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) 2011-13 के अनुसार, बिहार में प्रति एक लाख जन्मों पर मातृ मृत्यु अनुपात 208 है तथा वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2012-13 के अनुसार, राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में मातृ मृत्यु

▫ पीएच.डी. शोधार्थी, जनसंचार विभाग, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

अनुपात प्रति एक लाख जन्म पर 282 दर्ज की गई है, लेकिन राष्ट्रीय औसत से तुलना की जाए, तो राज्य का मातृ मृत्यु दर काफी अधिक है। बिहार में कुपोषण, खून की कमी के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव मातृ मृत्यु दर की प्रमुख वजह है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने एवं संस्थागत प्रसव को प्रौन्नत करके सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2005 से 'जननी सुरक्षा योजना' का सूत्रपात किया गया। स्वास्थ्य कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1 जून, 2011 को 'जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम' (जे.एस.एस.के.) की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं तथा जन्म से 30 दिनों के भीतर तक बीमार नवजात शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की गई है।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन एवं सर्वसाधारण जानकारी एवं जनता के बीच प्रचार-प्रसार हेतु जिला स्तर से विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा सूचना, शिक्षा, और संप्रेषण का काम संचालित किया जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायक नर्स दाई (एएनएम) के सहयोग से लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। जिसमें जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के इकाइयों में सभी प्रमुख स्थानों मुख्य द्वार, प्रसूति कक्ष, महिला एवं नवजात शिशु वार्ड एवं बाह्य रोगी कक्ष पर होर्डिंग, दीवाल लेखन एवं प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व जाँच के दौरान दिए जाने हेतु एक पृष्ठ की पम्पलेट या पर्चे का मुद्रण किया गया है। इसके अलावा स्वंयसेवी संगठन अपने क्षेत्र में कार्यकर्ता के द्वारा समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीण लोगों को जागरूक करती है।

संचार माध्यमों के प्रचार-प्रसार के बाद भी ग्रामीण महिलाओं में कार्यक्रम और इसमें होने वाले लाभ के प्रति जागरूकता की कमी देखी गई है। इन समस्याओं की पड़ताल करना वर्तमान समय में बहुत अधिक प्रासंगिक है। इसके आधार पर ग्रामीण स्तर पर मातृ स्वास्थ्य सम्बंधी कार्यक्रम क्रियान्वयन को मजबूत बनाने की दिशा में तथा प्रभावी स्वास्थ्य संचार की रणनीति विकसित करने में सहायक होगा।

शोध के उद्देश्य

- कार्यक्रम के बारे में ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता का अध्ययन करना।
- जागरूकता अभियान के प्रति महिलाओं की राय जानना।
- कार्यक्रम के अंतर्गत मिलने वाली निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी का पता लगाना।
- संदेश तथा जानकारी देने में प्रभावकारी माध्यम का पता लगाना।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध विशय वर्णनात्मक शोध अभिकल्प पर आधारित है। जिसमें सर्वेक्षण विधि से तथ्यों एवं आंकड़ों को एकत्रित किया गया है। शोध अध्ययन उत्तर बिहार स्थित मुजफ्फरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में है। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार में स्थित है। मुजफ्फरपुर जिले में 16 प्रखंड, 387 पंचायत तथा 1811 गांव है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 90 प्रतिशत जनसंख्या जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में एवं लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। मुजफ्फरपुर की कुल जनसंख्या 4,801,062 है। जिले में साक्षरता दर 63.43 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता दर 71.28 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 54.67 प्रतिशत है। सर्वेक्षण विधि में अत्यंत संरचित अनुसूची के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से आंकड़ों का संकलन किया गया। उत्तरदाताओं का चयन असम्भावित निदर्शन (Non-probability Sampling) के माध्यम से किया गया। सर्वेक्षण के लिए उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के द्वारा जिले स्थित 2 प्रखंड (मुशहरी और मुरौल) में से चुने गए 4 गांवों में से कुल 200 लक्षित प्रजनन आयु-समूह की विवाहित महिलाओं का चयन किया गया जिसने जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ लिया है और जो प्रश्नों का जवाब दे सकें। लक्षित उत्तरदाताओं की पहचान आशा कार्यकर्ता के माध्यम से की गई है। चयन के दौरान उन्हीं गांवों को शोध अध्ययन के लिए शामिल किया गया, जो सड़क मार्ग से जुड़े हों।

संकलित तथ्यों के आधार पर परिणामों की व्याख्या

सारणी और ग्राफ संख्या-1

कार्यक्रम के बारे में जानकारी कहां से पता चली

माध्यम	संख्या	प्रतिशत
आशा	185	92.5
आंगनवाडी	6	3.0
रेडियो	1	.5
टेलीविजन	1	.5
मोबाइल	6	3.0
अन्य	1	.5
कुल	**200**	**100.0**

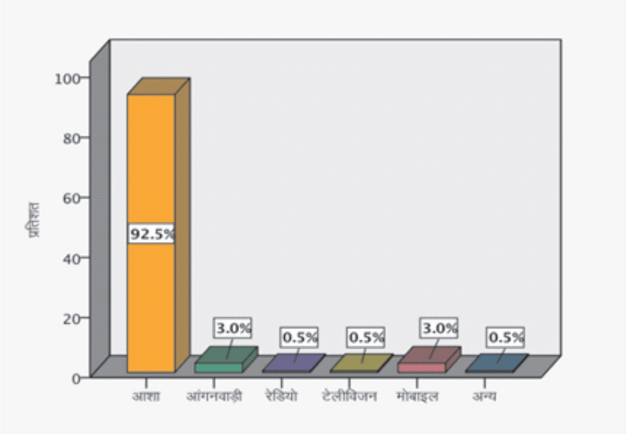

सारणी और ग्राफ संख्या 1 के अनुसार स्पष्ट है कि जहां सबसे अधिक 92.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को आशा कार्यकर्ता से जानकारी मिलती है, वहीं आंगनवाड़ी सेविका, मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन एवं अन्य माध्यम जैसे कि पड़ोसी आदि से जानकारी लेने वालों का प्रतिशत कम है।

सारणी और ग्राफ संख्या-2
स्वास्थ्य सम्बन्धित जागरूकता अभियान होने की जानकारी

मत	संख्या	प्रतिशत
हॉ	62	31.0
नहीं	71	35.5
पता नहीं	67	33.5
कुल	200	100.0

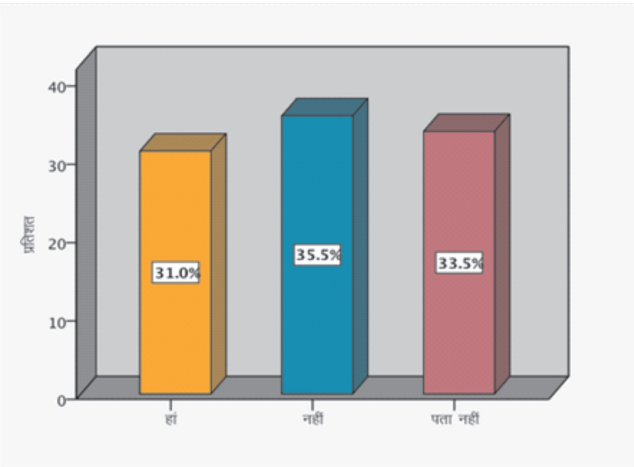

उत्तरदाता गांव में स्वास्थ्य सम्बन्धित जागरूकता अभियान नहीं होने की बात को स्वीकार करते हैं। 33.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं पता। वहीं 31 प्रतिशत उत्तरदाता जागरूकता अभियान होने की बात को स्वीकार करते हैं।

सारणी और ग्राफ संख्या-3
कार्यक्रम का लाभ किसके लिए है

मत	संख्या	प्रतिशत
जवाब नहीं	99	49.5
हॉ	49	24.5
नहीं	52	26.0
कुल	200	100.0

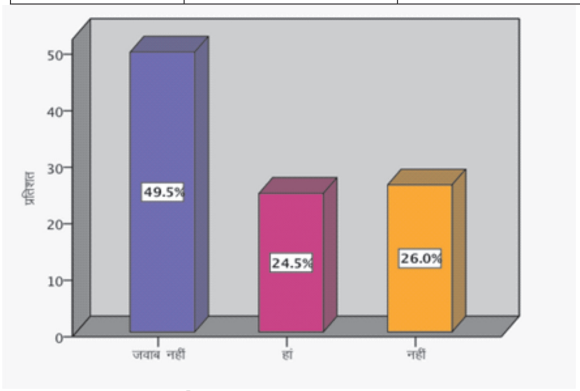

सारणी और ग्राफ संख्या 3 के अनुसार, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ किसके लिए है इस सम्बन्ध में गरीबी, अशिक्षा एवं प्रचार-प्रसार की कमी के कारण 49.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई जवाब नहीं दिया। 26 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें कुछ नहीं पता। 24.5 प्रतिशत उत्तरदाता जानकारी रखते हैं।

सारणी एवं ग्राफ संख्या-4
कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि मिली थीं

मत	संख्या	प्रतिशत
हॉ	162	81.0
नहीं	38	19.0
कुल	200	100.0

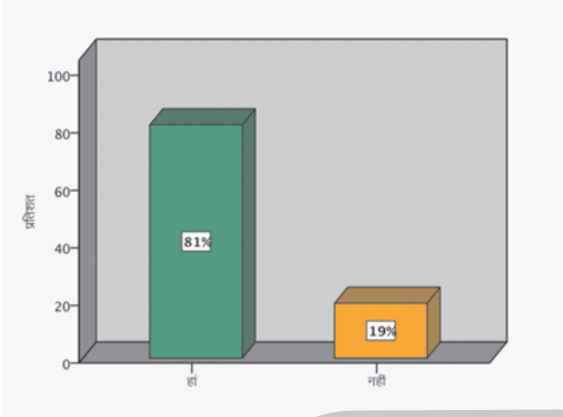

सारणी और ग्राफ संख्या 4 के अनुसार, 81 प्रतिशत उत्तरदाता प्रोत्साहन राशि मिलने की बात को स्वीकार करते हैं। वहीं 19 प्रतिशत उत्तरदाता का मानना है कि प्रोत्साहन राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं मिली।

सारणी एवं ग्राफ संख्या-5

प्रोत्साहन राशि कितनी मिली

मत	संख्या	प्रतिशत
1400 रू से कम	2	1.0
1400 रू	160	80.0
अभी तक नहीं	38	19.0
कुल	200	100.0

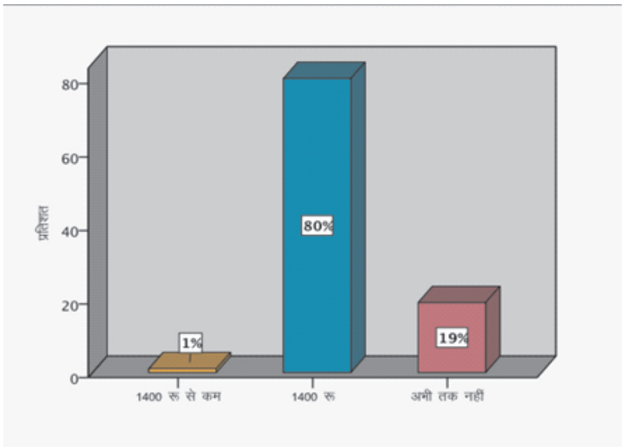

उपरोक्त सारणी एवं ग्राफ से स्पष्ट है कि सबसे अधिक करीब 80 प्रतिशत उत्तरदाता 1400 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलने की बात को स्वीकार करते हैं। वहीं 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि फंड की समस्या के कारण राशि अभी तक नहीं मिली।

सारणी एवं ग्राफ संख्या- 6

मत	संख्या	प्रतिशत
प्रसव के तुरंत बाद	89	44.5
बहुत बाद में	71	35.5
नहीं मिला	40	20.0
कुल	200	100.0

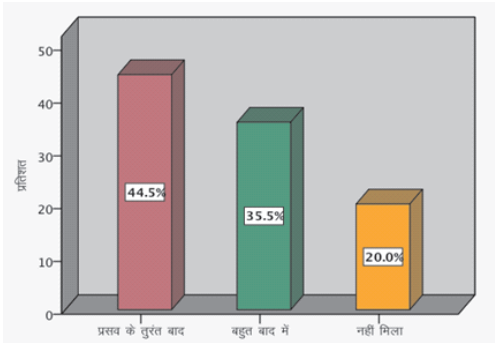

सारणी और ग्राफ संख्या 6 के अनुसार, 44.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि प्रसव के तुरंत बाद प्रोत्साहन राशि मिली। वहीं 35.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें बहुत बाद में राशि मिली। करीब 20 प्रतिशत उत्तरदाता का मानना है कि 1400 रुपये की प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिली।

सारणी और ग्राफ संख्या- 7

निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी

मत	संख्या	प्रतिशत
जवाब नहीं	20	10.0
हॉ	123	61.5
नहीं	57	28.5
कुल	200	100.0

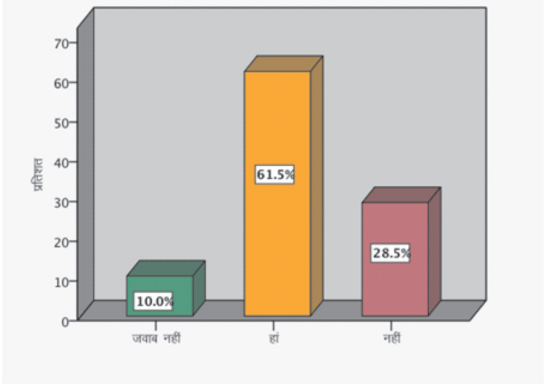

सारणी और ग्राफ से स्पष्ट है कि 61.5 प्रतिशत उत्तरदाता सरकार द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी रखते हैं। 28.5 प्रतिशत उत्तरदाता जानकारी नहीं रखते। वहीं 10 प्रतिशत उत्तरदाता स्वास्थ्यकर्मियों की लापरवाही, गरीबी, अशिक्षा के कारण इस सम्बंध में कोई जवाब नहीं दिया।

सारणी और ग्राफ संख्या- 8

मत	संख्या	प्रतिशत
हॉ	112	56.0
नहीं	61	30.5
पता नहीं	27	13.5
कुल	200	100.0

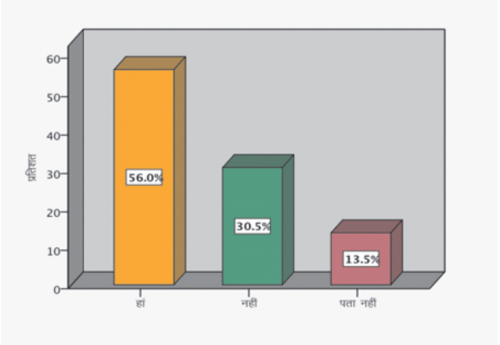

सारणी और ग्राफ संख्या 8 के अनुसार, 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिला। लगभग 30.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलने की बात कही। वहीं 13.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता।

सारणी और ग्राफ संख्या-9

मत	संख्या	प्रतिशत
हॉ	155	77.5
नहीं	45	22.5
कुल	200	100.0

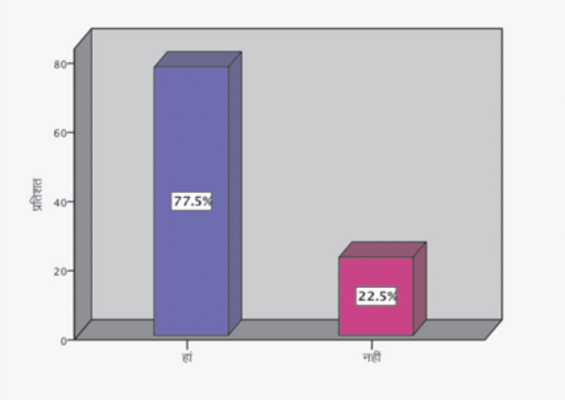

सारणी और ग्राफ संख्या 9 के अनुसार, 77.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें प्रसूति वाहन के बारे में जानकारी है। वही 22.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है।

सारणी और ग्राफ संख्या-10

मत	संख्या	प्रतिशत
हॉ	78	39.0
नहीं	117	58.5
पता नहीं	5	2.5
कुल	200	100.0

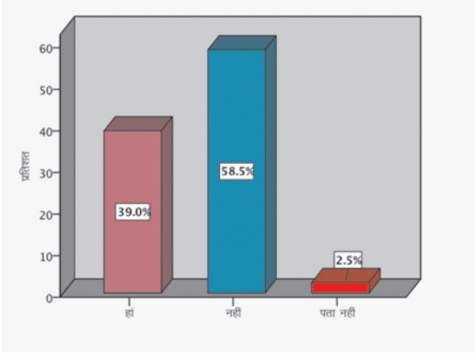

उपरोक्त सारणी और ग्राफ से स्पष्ट है कि 58.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को प्रसूति वाहन की सुविधा नहीं मिली। वही 39 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें प्रसूति वाहन की सुविधा मिली। 2.5 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जिन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं पता।

सारणी और ग्राफ संख्या-11

मत	संख्या	प्रतिशत
जवाब नहीं	24	12.0
पूर्ण संतुष्ट	62	31.0
आंशिक संतुष्ट	59	29.5
संतुष्ट नहीं	55	27.5
कुल	200	100.0

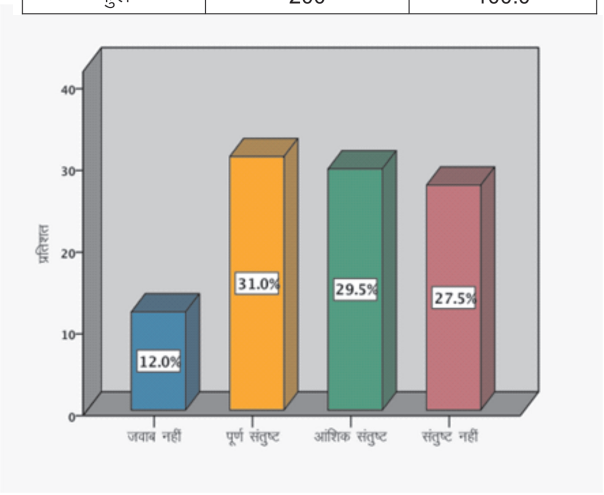

सारणी और ग्राफ संख्या 11 के अनुसार, 31 प्रतिशत उत्तरदाता कार्यक्रम के अंतर्गत मिलने वाली निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं से पूर्ण संतुष्ट हैं। 29.5 प्रतिशत उत्तरदाता आंशिक संतुष्ट है। वहीं 27.5 प्रतिशत उत्तरदाता का मानना है कि वे निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं से संतुष्ट नहीं है। जबकि 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वास्थ्यकर्मियों का कड़ा व्यवहार, पूर्ण राशि का अभाव के कारण इस सम्बन्ध में कोई जवाब नहीं दिया।

सारणी और ग्राफ संख्या-12

संचार माध्यम द्वारा दी जाने वाली कार्यक्रम सम्बंधित संदेश

मत	संख्या	प्रतिशत
हॉ	30	15.0
नहीं	126	63.0
कह नहीं सकते	44	22.0
कुल	200	100.0

उपरोक्त सारणी और ग्राफ से स्पष्ट है कि 63 प्रतिशत उत्तरदाता जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में संचार माध्यम द्वारा दी जाने वाली संदेश और जानकारी को प्रभावकारी नहीं मानते हैं। सिर्फ 15 प्रतिशत उत्तरदाता कार्यक्रम सम्बंधित दी जाने वाली संदेश और जानकारी को प्रभावकारी मानते हैं। वही 22 प्रतिशत उत्तरदाता का मानना है कि वे कह नहीं सकते।

निष्कर्ष

- अध्ययन से प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में कुल 200 उत्तरदाताओं में सबसे अधिक लगभग 93 प्रतिशत उत्तरदाताओं को आशा कार्यकर्ता से जानकारी मिलती है। कार्यक्रम सम्बंधित जानकारी देने में आशा कार्यकर्ता एक बहुत बड़ा माध्यम है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त गांव में कार्यक्रम से सम्बंधित जानकारी देने में अन्य प्रचार-प्रसार माध्यमों की पहुंच की कमी है।
- गांव में स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता अभियान बहुत लंबे अंतराल पर किया जाता है। प्रचार-प्रसार की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है।
- जहां 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 1400 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलने की बात को स्वीकार किया, वहीं राशि प्राप्त करने में समस्याओं पर उत्तरदाताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि फंड नहीं होने की वजह से उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। करीब 20 प्रतिशत उत्तरदाता का मानना है कि 1400 रुपये की प्रोत्साहन राशि पूर्ण रूप से अभी तक नहीं मिली।
- सरकार द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में करीब 62 प्रतिशत उत्तरदाताओं को जानकारी है। 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलने की बात को स्वीकार किया। अधिकांश उत्तरदाता कार्यक्रम के अंतर्गत मिलने वाली निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं से पूर्ण संतुष्ट हैं। वहीं कुछ उत्तरदाता अस्पताल प्रबंधन का रवैया, स्वास्थ्यकर्मियों की लापरवाही, सुविधाएं मिलने में विलंब आदि के कारण असंतुष्ट भी है।
- 58.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि प्रसूति वाहन की सुविधा नहीं मिली। प्रसव के समय महिलाएं अपने खर्चें से अस्पताल जाती है। फोन करने पर भी वाहन की सुविधा नहीं मिलती।
- उत्तरदाताओं ने स्वास्थ्यकर्मियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही, उपेक्षा, अज्ञानता आदि के कारण जवाब देने में बेरुखी दिखाई।
- 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में संचार माध्यम द्वारा जो संदेश और जानकारी दी जाती है वह प्रभावकारी नहीं हैं। वजह स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा दी जाने वाले उपयुक्त सलाह की कमी, प्रचार-प्रसार वाहनों द्वारा दी जाने वाले संदेश स्पष्ट नहीं होना आदि है।

इस प्रकार लोगों की उदासीनता के कारण ग्रामीण जन न तो अपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को समझ पाते हैं और न ही वे स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली व्यवस्था की कार्यविधि को जान पाते हैं। अतः जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमों में संचार माध्यमों की गतिविधियों को तेज करने के लिए राज्यों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रणनीतिक स्वास्थ्य संचार प्रयासों को मजबूत बनाना तथा हर स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किए जाने की आवश्यकता है। जन समुदाय को अधिक से अधिक जागरूक करने की जरूरत है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली के प्रदर्शन को सुदृढ़ करने की जरूरत है।

संदर्भ सूची :

- नायर, पी. (2010 जुलाई-सितंबर). संचार अध्ययनों में शोध विधियाँ-समग्र दृष्टि. मीडिया मीमांसा, पी 17.
- प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान (2012-13). जिला स्वास्थ्य समिति, मुजफ्फरपुर, बिहार, पी 333.
- भारत की जनगणना (2011). जिला जनगणना हैण्डबुक, सिरीज 11, बिहार, पी.
- मुखर्जी, आर. सामाजिक शोध एंड सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पीपी 161-164.
- सुंदररामन, टी. (फरवरी, 2016). भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र रू दृष्टिकोण और भावी रूपरेखा. योजना, पी 10.
- शर्मा, जी. (2010 अक्टूबर). स्वस्थ बिहार मुहिम से बढ़ रही है स्वास्थ्य सुविधाएँ, योजना, पी 31.

- स्वास्थ्य सम्बंधी प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा, स्वस्थ बिहार, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पीपी 7-9.
- संकल्प (2012). स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पीपी 1-2.
- रिपोर्ट कार्ड (2015). न्याय के साथ विकास यात्र सुशासन का 10वां वर्ष, बिहार सरकार, पी 43
- वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण फैक्ट शीट. बिहार अ०फिस द रजिस्ट्रार एंड सेंसस कमिश्नर, भारत मिनिस्ट्री अ०फ होम अफेयर्स, भारत सरकार, पी 133.
- एमएमआर बुलेटिन, एसआरएस आरजीआई. (2010-12). पी 1.

  (2016, May 06). Retrieved from Censusindia.gov.in
- (2016, April 10). Retrieved from http://hi.vikaspedia.in/health/women-health/pregnancy-health. P.
- (2015, April 19). Retrieved from http://hi.m.wikipedia.org/wiki/बहिार. पी.
- (2016, April 30). Retrieved from http://nrhm.gov.in/nrhm-components/rmnch-a/maternal-health/background.html. P.
- (2016, December 20). Retrieved from nrhm.gov.in/images/pdf/media/publication/Annual_Report-Mohfw.pdf. P 51.

❑❑❑